Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 17-2015] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 28, 2015 (VAISAKHA 8, 1937 SAKA)

CONTENTS

		Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government . .	117— 124
PART I-A—	Notifications by Local Government Department . .	Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners . .	Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commission of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India . .	Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices . .	81—85
PART III-A—	Notifications by Universities . .	Nil
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices . .	Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India . .	Nil
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature . .	Nil
SUPPLEMENT PART I—	. .	Nil
SUPPLEMENT PART II—	. .	Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT —Contents	. .	Nil
Ditto	PART I—Act . .	Nil
Ditto	PART II—Ordinances . .	Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation . .	Nil
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements . .	Nil

PART—I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

HARYANA GOVERNMENT

GRIEVANCES DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 2015

No. 5/1/2010-1DG.—The Governor of Haryana is pleased to remove the following persons from the membership of District Public Relations and Grievances Committee, Rohtak Jhajjar & Gurgaon with immediate effect constituted vide Haryana Government Notification No. 5/1/2010-1D.G, dated 13th April, 2015 as under :—

District Public Relations & Grievances Committee, Rohtak

1. Smt. Kanta Kalmariya, House No. 790/12, Salara, Mohalla Rohtak.

District Public Relations & Grievances Committee, Jhajjar

1. Sh. Kanwar Singh Malhan, Village & PO Subana, Tehsil & District Jhajjar.

District Public Relations & Grievances Committee, Gurgaon

1. Smt. Sudha Yadav, 258, Sector 10-A, Gurgaon.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2015

संख्या रा०नि०आ०/2ई-II/2015/5053.—राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई, 2014 के निरन्तर में निम्न शुद्धिपत्र अधिसूचित किया जाता है—

अधिसूचना क्रमांक	पैरा नं०	चुनाव प्रतीकों की सूची की श्रेणी	क्रम संख्या	चुनाव प्रतीक जो पढ़ा जाए	के स्थान पर
रा0नि0आ0/3ई0-II/2014/1897 दिनांक 11 जुलाई, 2014	1	'घ', पंचायत समिति सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक	26	कार	रोड रोलर

आदेश द्वारा,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 24th March, 2015

No. 64-Agri.II (1)-2015/3968.—The Governor of Haryana is pleased to constitute the District Level Committee (DLC) for selecting the Best Primary Worker (BPW) under the Scheme of Improvement of Agriculture Statistics.

District Level Committee (DLC)

1	Deputy Director, Agriculture at concerned District	Chairman
2	Assistant Statistical Officer (ASO), Agriculture at concerned District	Member Secretary
3	Statistical Assistant at concerned District	Member
4	Any one officer (Class-II) nominated by Deputy Director, Agriculture	Member

1. The term of the Committee will be three years.

2. The Committee will finalize the names of the Best Primary Workers (BPW) on the basis of the points such as :-

- Timely Submission of form by the Primary Worker.
- Timely Submission of datas.
- Good-co-ordination with farmers.
- Good Work efficiency judged by the members of the committee.

3. The Committee shall meet at least once in six months or twice in a year to review the implementation of the Scheme.

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अप्रैल, 2015

क्रमांक 129–कृषि–II(1)–2015/7140.–हरियाणा के राज्यपाल भारत सरकार के कृषि यन्त्रीकरण के उप–लक्ष्य (सब–मिशन) के परिचालन मार्गदर्शनों (एस एम ए एम) के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस एल ई सी) का गठन करते हैं। समिति के मुख्य कार्य उप–लक्ष्य (सब–मिशन) के लागूकरण के लिए राज्य नोडल विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना की विधीक्षा करना होगा। एस एल ई सी नोडल तथा अन्य लाईन विभाग के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से हरियाणा राज्य के मिशन (लक्ष्य) घटकों के लागूकरण का निरीक्षण करेगी। यह उपयुक्त पॉलिसी सूत्रीकरण के लिए कार्यकारी समिति को निवेश (इनपुट) भी मुहैया करेगी। समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगीः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/प्रधान सचिव, कृषि	अध्यक्ष
अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (कृषि इंजीनियरिंग)	सदस्य
फार्म मशीनरी तथा पावर इंजीनियरिंग,/सी सी एस एच ए यू, हिसार के विभागाध्यक्ष	सदस्य
निदेशक एफ एम टी टी आई, हिसार	सदस्य
महानिदेशक/निदेशक कृषि	सदस्य सचिव
महानिदेशक/निदेशक उद्यान	सह–सदस्य–सचिव

समिति के मुख्य कार्यः

कृषि विभाग/विभाग का कृषि इंजीनियरिंग अनुभाग इस लक्ष्य (मिशन) के लागूकरण के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी/विभाग होगा। यह एस.एल.ई.सी. को आवश्यक सहायता मुहैया कराएगा तथा निम्नलिखित कार्य करेगाः–

उन्नत उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए विशिष्ट अवस्थिति लाभ तथा सरलतम अनुकूलनशीलता सहित मुख्यतः फार्म यन्त्रीकरण वृद्धि पर फोकस करते हुए 2 के डब्ल्यू/एच ए तक फार्म पावर उपलब्धता प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए मिशन लागूकरण योजना (एम आई पी) तैयार करना।

अनुबन्ध–III पर फार्मूला (सूत्र) के अनुसार फार्म पावर उपलब्धता के अनुसार जिलों की सूची बनाना/लक्ष्य मानदण्डों के अनुसर वार्षिक कार्य योजना के अधीन जिलों का चयन करना।

ऐसी मशीनों तथा उपकरणों की निर्देशात्मक सूची तैयार करना जो मिशन के अधीन आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त न हो। नकारात्मक सूची तैयार करते समय, राज्य को विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए जिसमें ऐसे तथ्य शामिल हो कि क्या उपकरण/मशीनरी आर्थिक सहायता के बिना वाणिज्यिक रूप से चलाई जा सकती है।

राज्य सरकार के पास उपलब्ध विषय–वस्तु विशेषज्ञ (कृषि इंजिनियरिंग) की सेवाओं का सम्भव सीमा तक उपयोग करना। मिशन कार्यक्रमों में राज्य में कार्य करने वाली के वी के, एस ए यू तथा आई सी ए आर संस्थाएं।

वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा संसूचित राज्य की प्रयोगात्मक लागत को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध–VII के अनुसार मि"ान के लक्ष्यों तथ उद्दे"यों के अनुरूप वार्षिक राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करना।

एस सी पी के लिए कुल आबंटन का 20 प्रतिशत होगा। एस सी/एस सी किसानों को आबंटन जिले में उनकी जनसंख्या के आनुपातिक किया जाएगा। आबंटन का 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को ईयरमार्क किया जाएगा। आबंटन का कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए किया जाएगा।

वार्षिक कार्य योजना के आबंटन का 10 प्रतिशत निम्नलिखित उददेश्यों को पूरा करने के लिए लचीली–निधि (फलैकसी फंड) के अनुसार ईयरमार्क किया जाएगाः–

(क) एस एम ए एम के सम्पूर्ण लक्ष्य के भीतर स्थानीय आव"यकताओं तथा अपेक्षा को पूरा करने के लिए राज्यों को लचीलापन मुहैया कराने के लिए।

(ख) स्कीम तथा इसके प्रत्याक्षित परिणामों (निष्कर्षों) के सम्पूर्ण लक्ष्यों के भीतर मार्गद"ाी (पाइलट) अभिनव तथा उन्नत कार्यक्षमता के लिए।

(ग) कृषि यन्त्रीकरण सैक्टर में प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में अल्पीकरण/पुनरुद्धार कार्यकलाप करने के लिए।

ऐसे विनिर्माताओं/प्रदायकों का सहयोग प्राप्त करना जिन्होंने एफ एम टी टी आई या कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचान की गई किसी संस्था से उनके उत्पाद परीक्षित किए हैं तथा एस एस ए एम के विभिन्न घटकों के अधीन आपूर्ति करने के लिए गुण निरीक्षण तथा खेत कार्य मूल्यांकन के आधार पर कृषि मशीनरी तथा उपकरण की लागत नियत की है।

अन्य स्कीमों के साथ वार्षिक कार्य योजना का उचित एकीकरण सुनिश्चित करना जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) तथा बागबानी इत्यादि के समेकित विकास के लिए मिशन (एम आई डी एच)।

जिला वार कार्य योजना को राज्य कार्य योजना में संकलित करना तथा अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना तथा उसके बाद उसे ई सी को भेजना।

लागू करने वाले संगठनों के लिए डी ए सी से निधियां प्राप्त करना तथा कार्यक्रमों के लागूकरण का निरीक्षण करना, मानीटर करना तथा पुनरीक्षण करना।

राज्य स्तर पर सभी हितबद्ध समूहों/संघों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ग्रासरुट स्तर तक परिचालन सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) समर्थ प्रबन्धन प्रणाली।

अपने राज्यों मे लक्ष्य (मिशन) के कार्य को निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र मूल्यांकन करना।

राज्य के कुल आबंटन का 1 प्रतिशत प्रशासकीय तथा अन्य फुटकर खर्चों के लिए ईयरमार्क किया जा सकता है। 1 प्रतिशत की सीमा से अधिक खर्च को राज्यों द्वारा उनके अपने स्त्रोतों से पूरा किया जाएगा।

गठित समिति किसी अन्य सदस्य या कृषि इंजिनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ को सहयोजित करने या इसी प्रकार के इसके विचार विमर्श के लिए स्वतन्त्र होगी। समिति के सदस्य उनके अपने अपने सम्बन्धित विभाग/संगठन से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेंगे।

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 23rd April, 2015

No. 129-Agri-II (1)-2015/ 7140.— The Governor of Haryana is pleased to constitute a State Level Executive Committee (SLEC) headed by Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Agriculture Department as per operational guidelines of Sub-Mission of Agricultural Mechanization (SMAM) of Govt. of India. The main function of the Committee will be to vet the Annual Action Plan prepared by the State Nodal Department for implementation of the Sub-Mission. The SLEC will oversee the implementation of components of the mission in the State through regular meetings with the nodal and other line departments. It will also provide inputs to the Executive Committee for appropriate policy formulation. The constitution of the Committee will be as follows :—

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Agriculture	Chairman
Addl. Director/ Joint Director (Agricultural Engineering)	Member
Head of Department of Farm Machinery & Power Engineering, CCSHAU, Hisar	Member`
Director, FMTTI, Hisar	Member
Director General/Director Agriculture	Member Secretary
Director General/Director Horticulture	Co-Member Secretary

Main functions of the Committee:

Department of Agriculture shall be the Nodal Department at the State level for implementation of this Mission. It will provide necessary support to SLEC and will have the following functions:

To prepare Mission Implementation Plan (MIP) for entire plan period for achieving the farm power availability to 2 kW/ha, primarily focusing on increasing farm mechanization with location specific advantages and easier adaptability for improved production and productivity.

To list districts as per the farm power availability as per formula at Annexure-III. Select the districts under Annual Action Plan as per objective criteria.

To prepare indicative list of machines and equipment which should not be eligible for subsidy under the Mission. While preparing the negative list, State should consider various aspects including fact whether an equipment/machinery can be run commercially without subsidy.

To utilize, to the extent possible, services of Subject Matter Specialist (Agricultural Engineering) available with the State Government, KVKs, SAUs and ICAR Institutes functioning in the State in the Mission programmes.

To prepare annual State Level Action Plan in consonance with the goals and objectives of Mission as per Annexure-VII taking into account tentative outlay of State as communicated by Department of Agriculture & Corporation, Ministry of Agriculture, Govt. of India at the beginning of Financial Year.

20% of the total allocation for SCP will be earmarked. The allocation to SC farmers will be made proportionate to their population in the district. 30% of allocation will be earmarked for the women beneficiaries and at least 50% of the allocation shall be utilized for small and marginal farmers.

10% of the Annual Action Plan allocation would be earmarked as flexi-fund to meet the following objectives:

(a) To provide flexibility to States to meet local needs and requirement within the overall objective of SMAM.
(b) To pilot innovations and improved efficiency within the overall objectives of the Scheme and its expected outcomes.
(c) To undertake mitigation/restoration activities in case of natural calamities in the farm mechanization sector.

To enlist manufacturers/suppliers who have tested their products either from FMTTIs or any identified Institute by the Department of Agriculture & Corporation, Ministry of Agriculture, Government of India and fix the cost of agricultural machinery and equipment on the basis of quality inspection and field performance evaluation for supply under various components of SMAM.

To ensure suitable integration of Annual Action Plan with other schemes like Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY), National Food Security Mission (NFSM) and Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) etc.

To compile districtwise Action Plan into State Action Plan and submit to the State Level Committee for approval and thereafter forward the same to EC.

To receive funds from the Department of Agriculture & Corporation, Ministry of Agriculture, Govt. of India for implementing organizations and oversee, monitor & review implementation of the programmes.

To organize workshops, seminars and training programmes for all interest groups/associations at State level.

To operationalize Information Communication Technology (ICT) enabled management system upto grassroot level.

To conduct independent evaluation to assess the performance of the Mission in their States.

1% of total allocation to the State may be earmarked for administrative and other contingent expenses. Expenditure in excess of 1% limit will be met by the States from their own resources.

The Committee so constituted shall be free to co-opt any other Member or expert from the field of Agriculture Engineering etc. for deliberations. The Members of the Committees will draw their TA/DA from their respective Departments/Organizations.

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अप्रैल, 2015

क्रमांक 129–कृषि–II(1)–2015/7143.—हरियाणा के राज्यपाल भारत सरकार के कृषि यन्त्रीकरण के उप–लक्ष्य (सब–मि"ान) के परिचालन मार्गद"ानो (एस एम ए एम) के अनुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डी एल ई सी) का गठन करते है। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगेः–

उपायुक्त	अध्यक्ष
सहायक कृषि इंजीनियर	सदस्य सचिव
जिला बागवानी अधिकारी	सदस्य
समन्यवक के0 वी0 के0	सदस्य
नामांकित प्रगति"ाील किसान	सदस्य
लीड बैंक से प्रतिनिधि	सदस्य
उप निदे"ाक, कृषि	सह–सदस्य सचिव

डी एल ई सी निम्नलिखित कार्यों सहित परियोजना सूत्रीकरण, लागूकरण तथा मानीटरिंग के लिए म"ाीन के उद्दे"यों को आगे भेजने के लिए जिम्मेवार होगीः–

कृषि यन्त्रीकरण घटकों के लागूकरण के लिए फार्म (कृषि) पावर उपलब्धता के कम अनुपात के क्षेत्रों, छोटे तथा सीमांत जोत की बड़ी संख्या सहित क्षेत्रों की पहचान करना।

पारद"ार्ी तथा समयबद्ध रीति में एस एम ए एम का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों (किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), उपभोक्ता समूहों, सहकारी सोसाईटियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ) तथा ठेकेदारों) की पहचान करना। भाड़ा प्रथा केन्द्र स्थापित करने के लिए ठेकेदारों/एस0एच0जी की पहचान करना।

लाभार्थियों की मान्यता अपेक्षाओं के लिए बैकों के साथ सम्बन्ध बनाना।

सुनि"चत करना कि डी ए सी की विभिन्न स्कीमों के अधीन लाभ जैसे कि आर के वी वाई, एम आई डी एच, एन एम ओ ओ पी, एन एफ एस एम इत्यादि उसी लाभार्थी को बार बार नहीं दिए जा रहे हैं।

प्रत्येक घटक के अधीन भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों सहित जिला वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

उपबन्धों तथा मानकों के अनुसार उपकरण/निवे"ा की प्राप्ति का सबूत सुनि"चत करने के बाद लाभार्थियों की पहचान तथा चयन को सम्पूर्ण प्रक्रिया, लाभार्थियों के आवेदनों तथा वित्तीय सहायता के संवितरण की प्रक्रिया के लिए आनलाईन एप्लीके"ान साफ्टवेयर जहां जिला में ऐसा इन्फरास्ट्रक्चर है, का उपयोग करना।

कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य नोडल विभाग से निधियां प्राप्त करना।

आधार नम्बर के आधार पर किसानों/लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के सीधे अन्तरण के लिए प्रयास करना जहां अवसंरचना जिले में क्रिया"ाील है।

समूहो में गांव स्तर पर पंचायत भवन/मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुमोदित कार्यक्रमों किए गए सभी क्रियाकलापों तथा लाभार्थियों के नाम, उपगत खर्च इत्यादि के ब्योरों को मानीटर करना तथा प्रदर्"ात करना तथा वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा के उद्दे"य से सम्बन्धित ग्राम सभा के समक्ष इसे रखवाना।

कार्यक्रमों के लागूकरण के बाद उत्पादन तथा उत्पादकता के संघटन का अध्ययन करना तथा राज्य नोडल विभाग को रिपोर्ट भेजना।

जिले में कार्य करने वाली आई सी ए आर संस्थाएं/एस ए यू तथा के वी के जिला कार्य योजना के सूत्रीकरण, इसके लागूकरण तथा मानीटरिंग करने में तकनीकी सहायता मुहैया करांएगी। किसानों तथा प्रसारण कार्मिकों को प्र"िाक्षण देने के लिए तकनीकी अमला इन संगठनों से लिया जाएगा।

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 23rd April, 2015

No. 129-Agri-II (1)-2015/7143.—The Governor of Haryana is pleased to constitute a District Level Executive Committee (DLEC) headed by Deputy Commissioner as per operational guidelines of Sub-Mission of Agricultural Mechanization (SMAM) of Govt. of India. The others Members of the Committee are as under:

Deputy Commissioner	Chairman
Assistant Agricultural Engineer	Member Secretary
District Horticulture Officer	Member
Co- ordinator KVK	Member
Nominated Progressive farmer	Member
Representative from lead Bank	Member
Deputy Director Agriculture	Co- Member Secretary

DLEC will be responsible for carrying forward the objectives of the Mission for project formulation, implementation and monitoring with following functions:

To identify the areas of low ratio of farm power availability, areas with large number of small and marginal holdings for implementation of farm mechanization components.

To Identify beneficiaries (Farmers, Self Help Groups (SHGs), User Groups, Cooperative Societies, Farmer Producer Organizations (FPOs) and Entrepreneurs) to avail the benefits of SMAM in transparent and time bound manner. Identify entrepreneurs/SHGs to establish custom hiring centers.

To tie up with the Banks for credit requirements of the beneficiaries.

To ensure that the benefits under various schemes of DAC such as RKVY, MIDH, NMOOP, NFSM etc. are not extended repeatedly to the same beneficiary.

To prepare district Annual Action Plan with physical and financial targets under each component.

To utilize online application software for the entire process of identification and selection of beneficiaries, processing of applications and disbursement of financial assistance to the beneficiaries after ensuring the proof of procurement of equipment/inputs as per provisions and norms.

To receive funds from State Nodal Department for implementing the programmes.

To make efforts for direct transfer of financial assistance to the farmers/ beneficiaries on the basis of ADHAR No. where such infrastructure is functional in the district.

To monitor and display details of approved programme, all activities undertaken and name of beneficiaries, expenditure incurred etc. at the Panchayat Bhavan/prominent public place in the cluster/village level and get it placed before the concerned Gram Sabha annually from the point of social audit.

To study the impact on production and productivity after the implementation of the programmes and forward the reports to the State Nodal Department. ICAR Institutes/SAUs and KVKs functioning in the district will provide technical support in formulation of the district action plan, its implementation and monitoring. The technical staff will be sourced from these organizations for imparting training to the farmers and extension personnel.

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

53223–C.S.—H.G.P., Chd.